PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 019
दि. 19.05.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

दस साल बाद केरल में सत्ता परिवर्तन, वीडी सतीशन के नेतृत्व में लौटी यूडीएफ सरकार ने संभाली कमान

तिरुवनंतपुरम। V. D. Satheesan के नेतृत्व में सोमवार को केरल की राजनीति में एक नए दौर की औपचारिक शुरुआत हो गई। कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने पूरे दस वर्षों बाद राज्य की सत्ता में वापसी करते हुए नई सरकार का गठन किया। राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में V. D. Satheesan ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि उनके साथ 21 मंत्रियों ने भी एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह पल इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि करीब 60 वर्षों बाद यूडीएफ की पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली है।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री और सभी मंत्री लोक भवन पहुंचे, जहां Rajendra Vishwanath Arlekar ने उनके सम्मान में चाय समारोह आयोजित किया। इस दौरान मंत्रियों ने एक-दूसरे को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं और सरकार की आगामी प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा की। माहौल उत्साह और राजनीतिक ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री V. D. Satheesan ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह केवल सरकार परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों और विश्वास की वापसी का क्षण है।

राजधानी तिरुवनंतपुरम में सुबह से ही यूडीएफ समर्थकों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जब नई सरकार के मंत्री पहली कैबिनेट बैठक के लिए राज्य सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे, उसी दौरान शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन खराब मौसम भी समर्थकों के उत्साह को कम नहीं कर सका। सचिवालय परिसर के बाहर हजारों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए नई सरकार का स्वागत करते दिखाई दिए। भीड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, छात्र और आम नागरिक भी शामिल थे। कई समर्थक हाथों में यूडीएफ और कांग्रेस के झंडे लेकर मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगा रहे थे।

स्थिति इतनी भीड़भाड़ वाली हो गई कि सुरक्षा कर्मियों को मंत्रियों को सचिवालय के भीतर पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री V. D. Satheesan सबसे पहले अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी शुरुआती फाइलों पर हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। इस दौरान उनके सभी कैबिनेट सहयोगी पास के मीटिंग हॉल में मौजूद रहे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट रूम पहुंचे और पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक को लेकर राज्यभर में काफी उत्सुकता थी और बैठक में लिए गए फैसलों ने यह संकेत भी दे दिया कि यूडीएफ सरकार जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने जा रही है। सरकार ने महिलाओं, बुजुर्गों, आशा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। इन घोषणाओं को चुनाव के दौरान किए गए वादों की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।

कैबिनेट के सबसे चर्चित फैसलों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शामिल रही। सरकार ने घोषणा की कि 15 जून से राज्य की महिलाओं को Kerala State Road Transport Corporation यानी केएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राज्य की बड़ी महिला आबादी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और सरकार की सामाजिक कल्याण आधारित राजनीति को मजबूत करेगा।

इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अलग विशेष विभाग बनाने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि राज्य में तेजी से बढ़ रही वरिष्ठ नागरिकों की आबादी को देखते हुए उनकी जरूरतों और कल्याण योजनाओं के लिए समर्पित प्रशासनिक ढांचा जरूरी हो गया है। इस विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेंशन और सामाजिक सहायता से जुड़े कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।

नई सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को भी बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में 3,000 रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रही आशा कार्यकर्ताओं के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी भूमिका को देखते हुए सरकार ने इसे "सम्मान और सहयोग" का कदम बताया है।

सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। नई कैबिनेट ने घोषणा की कि राज्य के खजाने की वर्तमान स्थिति और वित्तीय हालात की जानकारी जनता के सामने रखने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि नई सरकार पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों और कर्ज स्थिति का विस्तृत विवरण सार्वजनिक कर सकती है। इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पहली कैबिनेट बैठक में वर्ष 2023 की 'नव केरल यात्रा' के दौरान Youth Congress नेताओं पर हुए हमले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन को भी मंजूरी दी गई। यूडीएफ लंबे समय से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता रहा है। अब सरकार बनने के बाद इस दिशा में औपचारिक कदम उठाया गया है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि V. D. Satheesan के नेतृत्व में बनी यह सरकार केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि केरल की राजनीति में नई रणनीति और नए प्रशासनिक दृष्टिकोण का संकेत भी है। दस वर्षों तक विपक्ष में रहने के बाद यूडीएफ ने जनता के बीच मजबूत वापसी की है और अब उसके सामने चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की बड़ी चुनौती होगी।

नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। यूडीएफ समर्थकों में उत्साह है, जबकि विपक्ष आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों और कार्यशैली पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल मुख्यमंत्री V. D. Satheesan की पहली कैबिनेट बैठक से यह साफ संकेत मिला है कि सरकार शुरुआत से ही जनहित और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपनी मजबूत राजनीतिक छाप छोड़ने की कोशिश करेगी।

पंजाब की सियासत में नया मोड़: निकाय चुनावों से पहले भाजपा की अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति तेज

नई दिल्ली। पंजाब की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत दे रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी राज्य में बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है और इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि पंजाब में इस बार मुकाबला केवल सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह इस बात की परीक्षा भी होगी कि क्या भाजपा राज्य में अपने दम पर एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर सकती है या नहीं। हालांकि वर्तमान में राज्य में पार्टी के पास केवल दो विधानसभा सीटें हैं, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर भाजपा खुद को लगातार मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।

पंजाब की राजनीति लंबे समय से त्रिकोणीय या द्विध्रुवीय रही है, लेकिन अब भाजपा इस समीकरण को चतुष्कोणीय बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत पार्टी न केवल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बल्कि सिख समुदाय के प्रभावशाली नेताओं को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है।

स्थानीय निकाय चुनावों को भाजपा अपनी सबसे अहम रणनीतिक परीक्षा मान रही है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर के ये चुनाव पार्टी के लिए यह समझने का मौका होंगे कि जमीनी स्तर पर उसकी स्वीकार्यता कितनी बढ़ी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन चुनावों में जीत-हार से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि विपक्षी दलों की स्थिति कितनी कमजोर या मजबूत दिखती है।

पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में Arvind Kejriwal की आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा था। उसी चुनाव में भाजपा को सीमित सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद से पार्टी ने राज्य में अपने संगठन को पुनर्गठित करने और विस्तार देने पर जोर दिया है।

भाजपा की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा राज्य के प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है। पार्टी लगातार पंजाब में कानून-व्यवस्था, गैंगस्टर संस्कृति, नशे की समस्या और आर्थिक चुनौतियों को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठा रही है। पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों पर जनता के बीच असंतोष है, जिसे राजनीतिक समर्थन में बदला जा सकता है।

इसके साथ ही भाजपा राज्य में अपने सिख नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रही है। पार्टी का फोकस यह है कि वह केवल एक बाहरी राजनीतिक ताकत के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के भीतर एक मजबूत वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में स्थापित हो सके। इसी के साथ संगठनात्मक स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं ताकि स्थानीय कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रिय भूमिका दी जा सके।

लोकसभा चुनावों के आंकड़े भी भाजपा के लिए उम्मीद जगाने वाले माने जा रहे हैं। पार्टी को राज्य में लगभग 18.5 प्रतिशत वोट मिले थे, जिसे नेतृत्व एक आधार के रूप में देख रहा है। पार्टी का मानना है कि यदि वह इस वोट प्रतिशत को और बढ़ाने में सफल रहती है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में उसका प्रभाव काफी बढ़ सकता है।

भाजपा की रणनीति में यह भी स्पष्ट है कि वह शिरोमणि अकाली दल जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि हाल के वर्षों में कई क्षेत्रीय दलों का जनाधार कमजोर हुआ है, इसलिए उनके साथ गठबंधन से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता।इसके बजाय पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान को मजबूत करने पर जोर दे रही है। भाजपा का मानना है कि पंजाब में मतदाता धीरे-धीरे एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं और पार्टी खुद को उसी विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पंजाब की राजनीति में आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। निकाय चुनावों के परिणाम यह तय करेंगे कि भाजपा की रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या वह वास्तव में राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है या नहीं।

फिलहाल राज्य में राजनीतिक माहौल लगातार बदल रहा है और सभी प्रमुख दल अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ऐसे में आने वाले समय में पंजाब की राजनीति एक बार फिर बेहद दिलचस्प और प्रतिस्पर्धी मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है।

जनसेवा पर फोकस: तमिलनाडु में 'अम्मा कैंटीन' के पुनरुद्धार का बड़ा फैसला, गुणवत्ता सुधार के निर्देश तेज

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति और सामाजिक कल्याण व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री M. K. Stalin ने राज्यभर में प्रसिद्ध 'अम्मा उनावगम' यानी अम्मा कैंटीनों के बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के आदेश जारी किए हैं। सरकार का यह फैसला आम लोगों को सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

राज्य सरकार के अनुसार, यह निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें कैंटीनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वाद को लेकर असंतोष जताया गया था। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यह मॉडल तभी प्रभावी रह सकता है जब इसमें लगातार सुधार और निगरानी बनी रहे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में ग्रेटर चेन्नई नगर निगम के अंतर्गत लगभग 383 अम्मा कैंटीनें संचालित हो रही हैं, जबकि राज्य के अन्य नगर निगमों और नगरपालिकाओं में करीब 237 कैंटीनें कार्यरत हैं। इन कैंटीनों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजाना कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे

गरीब, श्रमिक वर्ग और दैनिक वेतनभोगी लोगों को बड़ी राहत मिलती है।

सरकार ने यह भी बताया कि इन कैंटीनों में लगभग 20,000 प्रकार के भोजन से संबंधित सेवाएं और मेन्यू शामिल हैं, लेकिन कई जगहों पर गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता को लेकर शिकायतें मिली हैं। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री M. K. Stalin ने संबंधित विभागों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई योजना के तहत कैंटीनों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा। रसोई उपकरणों का आधुनिकीकरण, स्वच्छता मानकों में सुधार, और भोजन की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर अम्मा कैंटीन में परोसा जाने वाला भोजन न केवल सस्ता हो, बल्कि पौष्टिक और स्वादिष्ट भी हो।

राज्य सरकार के अनुसार, यह कदम केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक कल्याण दृष्टिकोण का हिस्सा है। अम्मा कैंटीन योजना को पहले से ही तमिलनाडु की सबसे सफल जनकल्याण योजनाओं में से एक माना जाता रहा है, जिसने शहरी गरीबों के लिए भोजन की उपलब्धता को आसान बनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पुनर्गठन से न केवल कैंटीनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। रसोई प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। राजनीतिक रूप से भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि अम्मा कैंटीन लंबे समय से तमिलनाडु की सामाजिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इस योजना को मजबूत और आधुनिक बनाकर सरकार एक बार फिर अपने कल्याणकारी मॉडल को जनता के सामने प्रभावी रूप में प्रस्तुत करना चाहती है।

फिलहाल सरकार ने सभी संबंधित नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि सुधार कार्य जल्द से जल्द शुरू किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कैंटीन में सेवा बाधित न हो। आने वाले महीनों में इस योजना के परिणाम राज्य के लाखों लोगों के दैनिक जीवन पर सीधा असर डाल सकते हैं।

तेल संकट की आहट: ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य तनाव से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूचाल का खतरा

पेरिस। वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर संकट की ओर बढ़ती दिख रही है, जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता पर बड़ा दबाव बन गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) ने सोमवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दुनिया के व्यावसायिक तेल भंडार तेजी से घट रहे हैं और मौजूदा स्थिति में केवल कुछ हफ्तों का ही स्टॉक बचा है। एजेंसी प्रमुख Fatih Birol ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव, विशेष रूप से ईरान युद्ध और Strait of Hormuz में संभावित व्यवधान, वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर डाल रहे हैं।

International Energy Agency के अनुसार, मौजूदा संकट को संभालने के लिए सदस्य देशों ने रणनीतिक तेल भंडार से प्रतिदिन लगभग 25 लाख बैरल तेल बाजार में जारी करना शुरू किया है। हालांकि एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह एक सीमित उपाय है और इन भंडारों का उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। पेरिस में आयोजित जी-7 देशों की वित्त मंत्रियों की बैठक में Fatih Birol ने कहा कि अगर स्थिति जल्दी सामान्य नहीं हुई तो ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच वैश्विक तेल भंडार में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में करीब 24.6 करोड़ बैरल तेल की कमी आई, जो हाल के वर्षों में सबसे तेज गिरावट मानी जा रही है। इसी के चलते मार्च में सदस्य देशों ने मिलकर 40 करोड़ बैरल तक के आपातकालीन तेल रिलीज का निर्णय लिया था, जिसे अब तक का सबसे बड़ा समन्वित हस्तक्षेप बताया जा रहा है। इसमें से लगभग 16.4 करोड़ बैरल तेल पहले ही बाजार में जारी किया जा चुका है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट केवल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भू-राजनीतिक अस्थिरता भी प्रमुख कारण है। ईरान और क्षेत्रीय तनाव के कारण Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ गया है, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। यदि इस जलमार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति लगभग तुरंत प्रभावित हो सकती है।

ऊर्जा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के मौसम की शुरुआत के साथ तेल की मांग और तेज होने वाली है। इस दौरान डीजल, पेट्रोल, विमान ईंधन और कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले उर्वरकों की मांग बढ़ती है, जिससे मौजूदा भंडार और तेजी से खत्म हो सकते हैं। इसके साथ ही परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि भी दबाव को और बढ़ाएगी।

International Energy Agency की नवीनतम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति में प्रतिदिन लगभग 39 लाख बैरल की कमी हो सकती है, जो पहले के 15 लाख बैरल के अनुमान से काफी अधिक है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पहले से अधिक अस्थिर हो चुकी है।

यदि स्थिति बिगड़ती है, तो इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर दिखाई देगा। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल की संभावना जताई जा रही है, जिससे दुनिया भर में महंगाई दर बढ़ सकती है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन लागत, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर इसका सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, ऐसे में वैश्विक कीमतों में किसी भी तरह की वृद्धि का असर घरेलू बाजार पर तुरंत दिखाई देता है।

Strait of Hormuz को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। यहां किसी भी तरह की बाधा या तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को एक झटके में प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है।

फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। आने वाले हफ्ते यह तय करेंगे कि यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अस्थायी झटका साबित होगा या एक बड़े ऊर्जा संकट की शुरुआत।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बात-बेबात और विवाद

इसमें दो राय नहीं कि देश के प्रतिष्ठित व शीर्ष पदों पर विराजमान व्यक्तियों को अपने संस्थानों व सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रखने में अतिरेक में सावधानी बरतनी चाहिए। उससे निकलने वाले शब्दों के अर्थों के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ऐसी ही चर्चा देश की शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के हालिया बयानों को लेकर हुई। बताया जाता है कि एक अधिवक्ता द्वारा सीनियर का दर्जा दिए जाने के बाबत दायर याचिका पर खिन्न मुख्य न्यायाधीश ने प्रासंगिक संदर्भ में जो कहा, उसको लेकर सवाल उठे। बताया जा रहा है कि 'उन्होंने मौखिक तौर पर कहा कि समाज में पहले से ऐसे परजीवी हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं... कुछ युवा ऐसे हैं, जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण 'कॉकरोच' की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उसमें से कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं।' निश्चय ही हाल के वर्षों में संपादक विहीन सोशल मीडिया में लोगों के अराजक व्यवहार को देखते हुए यह भले ही यह सत्य न हो, कुछ लोग इसे अर्धसत्य बताते हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से इस विषय पर संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने 'कॉकरोच' वाले बयान पर कहा है कि 'मीडिया ने उनके शब्दों को गलत ढंग से पेश किया।'

उन्होंने अपनी मौखिक टिप्पणी के बाबत कहा कि उनकी बातों को इस तरह पेश किया गया जैसे उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की हो। उनका कथन था कि उनकी टिप्पणी केवल उन लोगों के खिलाफ थीं, जिन्होंने फर्जी या नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में घुस आए हैं, इसलिए परजीवियों की तरह हैं। उनका इशारा न्यायापालिका पर होने वाले अनुचित हमलों की तरफ था। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों की कानून की डिग्रियों की जांच प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों द्वारा डाली जाने वाली सामग्री को देखकर उन्हें कई वकीलों की कानूनी डिग्रियों की प्रमाणिकता पर संदेह है। लेकिन इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों व सोशल एक्टिविस्ट ने सीजेआई की टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी हैं। राज्यसभा में एक राजद सांसद ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर मुख्य न्यायाधीश की भाषा को लेकर चिंता जतायी। उनका कहना था कि बेरोजगारों, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना 'कॉकरोच' व 'परजीवी' से करना लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने वाला लगता है। आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका से आशा की जाती है कि वह संवैधानिक संयम व गरिमा की अंतिम शरणस्थली बनी रहे। एक आरटीआई कार्यकर्ता का मानना है कि प्रश्न पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, ये व्यवस्था पर हमला नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाये रखने में भूमिका है।

उपभोक्ता व्यवहार परिवर्तन में वैश्विक संकट का हल

> "उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव की अपील की गई है जैसे—पेट्रोल और डीजल का सावधानी से उपयोग, सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो का अधिक इस्तेमाल और कार पूलिंग को बढ़ावा देने का आग्रह।

उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव की अपील की गई है जैसे—पेट्रोल और डीजल का सावधानी से उपयोग, सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो का अधिक इस्तेमाल और कार पूलिंग को बढ़ावा देने का आग्रह। सबसे गंभीर स्थिति होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से बनी है। कच्चे तेल और गैस से भरे सैकड़ों जहाज रास्तों में रुके पड़े हैं, जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। भारत ने अपने ऊर्जा भंडार के सहारे आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक संभालना आसान नहीं होगा। भारत की अर्थव्यवस्था भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। पेट्रोल, डीजल, गैस, डामर और यूरेनियम तक इसी मार्ग से आते हैं। ऐसे में आयात संकट गहराता जा रहा है और सीमित भंडार तेजी से घट रहे हैं।

हाल ही में हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को विश्व के लिए गंभीर और भयावह संकट बताया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल बलिदान देने तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक संकट के समय जिम्मेदारीपूर्ण जीवन जीने में भी है। भारत के सामने इस समय बड़ी चुनौती ऊर्जा आपूर्ति की है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते खाड़ी देशों से आता है।

इसी मार्ग से प्राकृतिक गैस, तारकोल और किसानों के लिए उर्वरक भी भारत पहुंचते हैं। लेकिन युद्ध के कारण यह रास्ता बाधित हो गया है। लगातार बढ़ती हिंसा और तबाही से साफ है कि शांति वार्ताएं फिलहाल केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं और युद्धरत देश टकराव की राह पर अड़े हैं। ऐसे में निकट भविष्य में होर्मुज मार्ग खुलने की संभावना भी कम नजर आ रही है, जिससे वैश्विक आर्थिक संकट और गहरा सकता है।

प्रधानमंत्री ने पूरे देश से अपने उपभोक्ता व्यवहार को बदलने की अपील की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जैसे भी हो, अपने पेट्रोल और डीजल की खपत घटाएं क्योंकि हमारे पास यथेष्ट तेल के कुएं नहीं और हम कच्च तेल बाहर से मंगवाते हैं। अब जब आयात बढ़ेगा तो जाहिर है, हमारे रुपये के मूल्य पर उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले उसका मूल्य लगातार घटता न जाए, इसलिए देश के पास उचित सोने के भंडार होने चाहिएं ।जो उसके विनिमय व्यवहार के काम आएं।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोने की गैर-जरूरी खरीद से बचने की अपील की है। भारत में विवाह आदि अवसरों पर सोना खरीदना परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की पहुंच से इसे दूर कर दिया है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह स्थिति और गंभीर हो गई है। कोविड के बाद शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध अब तक जारी है, वहीं चीन-ताइवान तनाव भी बढ़ता जा रहा है।

इन सभी घटनाओं का संयुक्त प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऊर्जा संकट, महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और बाजार की अस्थिरता बढ़ी है। इसका असर भारत सहित अनेक देशों पर दिखाई दे रहा है, जिससे आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ गई है।

विश्व में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हो चुकी है। भारत अपनी जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, इसलिए इस संकट का सीधा असर देश के भोजन, ईंधन और कृषि आपूर्ति पर पड़ना तय है। इस स्थिति से निपटने हेतु विदेशी मुद्रा बचाने और ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है।

इसी कारण उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव की अपील की गई है—पेट्रोल और डीजल का सावधानी से उपयोग, सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो का अधिक उपयोग और कारपूलिंग को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। माल ढुलाई में भी रेलवे सेवाओं के अधिक उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, हालांकि वर्तमान ढांचे में अभी पूरी तरह परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसे में सरकार के सामने मूल्य स्थिरता बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है, जबकि युद्ध का समाधान अभी दूर दिखाई देता है।

प्रेरणा

शब्दों की चुभन से जागती सामाजिक चेतना

व्यंग्य साहित्य की सबसे जीवंत और प्रभावशाली विधाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यह सीधे उपदेश देने के बजाय समाज की विसंगतियों को इस तरह सामने रखता है कि पाठक हंसते-हंसते भीतर तक असहज हो उठता है। व्यंग्य केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक चेतना का वह दर्पण है जिसमें समय का असली चेहरा दिखाई देता है। जब समाज में पाखंड बढ़ने लगता है, जब सच और झूठ के बीच की दूरी धुंधली होने लगती है, जब संवेदनाएं सुविधाओं के बोझ तले दबने लगती हैं, तब व्यंग्य अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनिल सोनी का व्यंग्य संग्रह 'शव संवाद' इसी भूमिका को बेहद गंभीरता और गहराई के साथ निभाता है। यह संग्रह पाठक को केवल मुस्कराने का अवसर नहीं देता, बल्कि उसे सोचने, ठहरने और अपने समय के भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। 'शव संवाद' शीर्षक ही अपने भीतर एक बेचैन करने वाला अर्थ समेटे हुए है। शव यानी ऐसी देह जिसमें जीवन समाप्त हो चुका हो और संवाद यानी विचारों का आदान-प्रदान। इन दोनों शब्दों का मेल यह संकेत देता है कि समाज में संवाद तो बचा हुआ है, लेकिन उसके भीतर की जीवंत चेतना धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। आज हर तरफ शोर है, बहसें हैं, टीवी स्टूडियो की चीखती आवाजें हैं, सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इन सबके बीच संवेदनशील मनुष्य कहीं खोता जा रहा है। लोग हर विषय पर बोल रहे हैं, लेकिन सच सुनने और स्वीकार करने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। अनिल सोनी इसी मृत होती सामाजिक चेतना की चीरफाड़ अपने व्यंग्य के माध्यम से करते हैं।

उनकी लेखनी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें कृत्रिम हास्य नहीं है। वे पाठक को हल्के-फुल्के चुटकुलों से नहीं बांधते, बल्कि शब्दों के भीतर ऐसी तल्खी पैदा करते हैं जो सीधे विवेक पर चोट करती है। वे लिखते हैं कि "व्यंग्य ने बुद्धिजीवी को कड़वाहट से भर दिया या वह व्यंग्य को कड़वा बना रहा है, इसी छटपटाहट का नाम है—शव संवाद।" यह पंक्ति केवल लेखक की मनःस्थिति नहीं, बल्कि हमारे समय के पूरे बौद्धिक समाज का बयान है। आज का बुद्धिजीवी सबसे ज्यादा असुरक्षित दिखाई देता है। वह सच को पहचानता है, व्यवस्था की विसंगतियों को समझता है, लेकिन उसकी आवाज धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। उसके भीतर प्रतिरोध की जगह एक अजीब तरह की थकान जन्म ले रही है।

अनिल सोनी ने अपने व्यंग्य में बुद्धिजीवी वर्ग पर जो कटाक्ष किया है, वह बेहद सटीक और मारक है। वे लिखते हैं कि बुद्धिजीवी ने सपने छोड़ दिए ताकि वह वास्तविकता को ठीक से देख सके, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि सही सोचना भी सपना लगने लगा है। यह कथन हमारे दौर की सबसे बड़ी त्रासदी को उजागर करता है। कभी समाज सामूहिक सपनों के सहारे आगे बढ़ता था। लोग बदलाव, समानता और न्याय के लिए संघर्ष करते थे। आज व्यक्ति केवल अपनी सुरक्षा और सुविधा तक सीमित हो गया है। सामूहिक चेतना धीरे-धीरे खत्म हो रही है। हर कोई व्यवस्था को बदलने के बजाय उसमें अपने लिए सुरक्षित जगह तलाशने में लगा है। यही कारण है कि समाज में प्रतिरोध की आवाजें कम होती जा रही हैं और समझौते बढ़ते जा रहे हैं।

'शव संवाद' आधुनिक मीडिया की मानसिकता पर भी तीखा प्रहार करता है। लेखक का यह कथन कि "भारत में व्यस्तता के दो कारण हैं—या तो मनोरंजन में व्यस्त हैं या किसी त्रासदी में व्यस्त हो सकते हैं" आज की सामाजिक स्थिति को बेहद गहराई से व्यक्त करता है। वर्तमान समय में त्रासदी भी मनोरंजन का हिस्सा बन चुकी है। किसी दुर्घटना, हत्या, युद्ध या राजनीतिक विवाद को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह एक तमाशा बन जाए। टीवी चैनलों की बहसें संवेदना पैदा करने के बजाय उत्तेजना पैदा करती हैं। लोग घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं, लेकिन किसी घटना का वास्तविक दुख उनके भीतर स्थायी असर नहीं छोड़ता। अगले दिन नया मुद्दा आ जाता है और पुरानी त्रासदी भुला दी जाती है। यह संवेदनहीनता केवल मीडिया की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अनिल सोनी का व्यंग्य यह भी बताता है कि आज विचार से ज्यादा प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो गया है। 'शव संवाद-37' में पोस्टर का प्रसंग इसी विडंबना को उजागर करता है। लेखक लिखते हैं कि पोस्टर बुद्धिजीवी से कहीं आगे निकल गए जबकि बुद्धिजीवी वहीं खड़ा रह गया। यह केवल राजनीतिक पोस्टरों की बात नहीं है, बल्कि उन तमाम नारों, अभियानों और दिखावटी आंदोलनों का प्रतीक है जो आज समाज में तेजी से पैदा होते और समाप्त हो जाते हैं। वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और उनका प्रचार आगे निकल जाता है। विचार और चिंतन की जगह अब शोर और प्रचार ने ले ली है। लोग नारे दोहराते हैं, ट्रेंड चलाते हैं और खुद को जागरूक समझने लगते हैं, जबकि वास्तविक समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। 'शव संवाद' की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह केवल व्यवस्था की आलोचना नहीं करता, बल्कि पाठक को भी कठघरे में खड़ा करता है। यह संग्रह हमें एहसास कराता है कि विसंगतियां केवल नेताओं, मीडिया या संस्थाओं में नहीं हैं, वे हमारे भीतर भी मौजूद हैं। हम भी धीरे-धीरे इतने सुविधाभोगी हो चुके हैं कि अन्याय देखकर चुप रह जाते हैं। हम सच जानते हुए भी उसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारी सुविधा प्रभावित हो सकती है। हम भ्रष्टाचार को गलत कहते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर उसी व्यवस्था का हिस्सा बनने से पीछे नहीं हटते। यही सामाजिक पाखंड अनिल सोनी के व्यंग्य का सबसे बड़ा विषय बन जाता है। व्यंग्य की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि वह पाठक को उसकी सहज स्थिति से बाहर निकाल दे। 'शव संवाद' यह काम पूरी ताकत के साथ करता है। इसमें हास्य है, लेकिन वह हल्का हास्य नहीं है जो कुछ पल की हंसी देकर समाप्त हो जाए। यह ऐसा हास्य है जिसके भीतर बेचैनी छिपी हुई है। पाठक मुस्कराता जरूर है, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक प्रश्न भी जन्म लेता है कि क्या सचमुच समाज इतनी तेजी से संवेदनहीन होता जा रहा है? यही प्रश्न इस व्यंग्य संग्रह को महत्वपूर्ण बनाता है।

आज जब साहित्य का एक बड़ा हिस्सा केवल मनोरंजन और त्वरित लोकप्रियता की ओर झुकता दिखाई देता है, ऐसे समय में 'शव संवाद' जैसी कृतियां साहित्य की वास्तविक भूमिका की याद दिलाती हैं। साहित्य केवल समय बिताने का साधन नहीं होता, बल्कि वह समाज की चेतना को जीवित रखने का माध्यम भी होता है।

Yogi, Dhami, Sawant, Bhupendra Patel क्या फिर से सत्ता में वापसी कर पाएँगे?

पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजे के बाद भाजपा गदगद है। बीजेपी का उत्साह चरम पर है और आने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव में भी बीजेपी के इस उत्साह को हम देख सकते हैं। बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाली है क्योंकि 2027 में कई ऐसे राज्यों में चुनाव है जहां बीजेपी सत्ता में है और वहां पर सत्ता बनाए रखने की चुनौती उसके पास रहने वाली है। बीजेपी एक चुनावी मिशन की तरह काम करती है। एक राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद वह अपने अगले लक्ष्य को लेकर तैयारियां शुरू कर देती है। उन्होंने इस दावा किया कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों के लिए चुनावी रणनीति बनाने की शुरुआत कर चुकी है और वहां पर कार्यकर्ताओं कोई कलेक्शन देश देने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालते ही चुनावी वादों पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाने तो शुरू कर ही दिये हैं साथ ही राज्य की राजनीति और प्रशासन में तेज बदलावों का दौर भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें राज्य की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उनके गढ़ में पराजित कर सत्ता तक पहुंचे सुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के केवल 48 घंटे के भीतर लगभग डेढ़ दर्जन बड़े निर्णयों की घोषणा कर यह संकेत दे दिया कि नई सरकार प्रशासनिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर व्यापक बदलाव चाहती है।

नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी। कोलकाता के रेड रोड क्षेत्र में सार्वजनिक नमाज पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया गया है। सरकार ने पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के साथ पूर्वी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद भाजपा की नजर अब 2027 में होने वाले सात राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है, जिनमें गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश प्रमुख हैं। पार्टी ने इन राज्यों में चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अगले वर्ष के चुनावी अभियान के लिए जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ कर दिया है। भाजपा के एक सूत्र ने कहा, "पांच राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब पार्टी का ध्यान अगले वर्ष सात राज्यों में होने वाले चुनावों पर केंद्रित हो गया है। कुछ स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें अब और तेज किया जाएगा।" पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों व नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। वह जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां अगले वर्ष गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है।

उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भाजपा की गतिविधियों का केंद्र रहने वाला है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अब लगातार यूपी के दौरे होते रहेंगे जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान उठाना पड़ा था इसलिए भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को लेकर खासा सतर्क है। माना जा रहा है कि यूपी के मामलों को सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखेंगे ताकि राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की हैट्रिक में कोई कमी नहीं रह जाये।

अभियान

सोने की चमक में छिपी बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और संस्कारों की विरासत

भारतीय समाज में शादी केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं मानी जाती, बल्कि यह भावनाओं, परंपराओं, संस्कारों और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं का उत्सव होती है। यहां विवाह का हर रंग, हर रस्म और हर वस्तु अपने भीतर एक गहरा सांस्कृतिक अर्थ समेटे रहती है। इन्हीं परंपराओं में सोने का विशेष स्थान सदियों से बना हुआ है। भारतीय शादी की कल्पना दुल्हन के सोने के गहनों के बिना अधूरी मानी जाती है। चाहे समय कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, चाहे फैशन की दुनिया में डायमंड, प्लेटिनम और डिजाइनर जूलरी का दौर क्यों न आ जाए, लेकिन भारतीय परिवारों में बेटी की शादी के समय सोना आज भी सबसे जरूरी और सबसे भावनात्मक उपहार माना जाता है।

दादी-नानी अक्सर कहा करती थीं कि "बेटी का असली सहारा उसका सोना होता है।" यह केवल एक कहावत नहीं थी, बल्कि उस दौर का जीवन अनुभव था जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हुआ करती थी। पुराने समय में महिलाएं घर और परिवार तक सीमित रहती थीं। उनके पास अपनी कमाई या व्यक्तिगत संपत्ति बहुत कम होती थी। ऐसे समय में शादी के दौरान दिया गया सोना ही उनका सबसे बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच माना जाता था। यही कारण है कि भारतीय परिवार अपनी क्षमता से बढ़कर भी बेटी के लिए सोने के गहने बनवाते थे। यह केवल दिखावे या सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं था, बल्कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता भी थी। भारतीय परंपरा में शादी में मिले गहनों को "स्त्रीधन" कहा गया है। स्त्रीधन का अर्थ केवल संपत्ति नहीं, बल्कि महिला का वह व्यक्तिगत अधिकार है जिस पर किसी और का दावा नहीं होता। धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं में भी यह माना गया कि विवाह के बाद महिला को मिले गहने और उपहार उसी के होते हैं। जब परिवार आर्थिक संकट से गुजरता, कठिन परिस्थितियां आतीं या किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ता, तब यही सोना घर का सहारा बनता था। यही वजह है कि दादी-नानी के समय में सोने को केवल आभूषण नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक माना जाता था।

भारतीय संस्कृति में सोने का संबंध केवल आर्थिक मजबूती से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों से भी जुड़ा हुआ है। सोने को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि जहां सोना होता है, वहां सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। विवाह के समय दुल्हन का सोने से सजा होना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि वह अपने नए घर में खुशियां, समृद्धि और सौभाग्य लेकर जा रही है। यही कारण है कि शादी के दिन दुल्हन को सिर से पांव तक सोने के गहनों से सजाने की परंपरा भारत के लगभग हर हिस्से में दिखाई देती है।

भारत के अलग-अलग राज्यों में सोने के गहनों की अपनी विशेष परंपराएं हैं। दक्षिण भारत में दुल्हन के लंबे हार और कमरबंद विशेष महत्व रखते हैं, तो राजस्थान और गुजरात में भारी कंगन, नथ और मांगटीका परंपरा का हिस्सा होते हैं। बंगाल में सोने की चूड़ियां और पारंपरिक हार विवाह की पहचान माने जाते हैं। पंजाब में दुल्हन के गहनों में शाही अंदाज दिखाई देता है। हर क्षेत्र में डिजाइन बदल जाते हैं, लेकिन सोने का महत्व समान बना रहता है। यह विविधता भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी दर्शाती है।

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय परिवारों में सोना केवल खरीदकर पहनने की चीज नहीं होता, बल्कि वह भावनाओं और स्मृतियों की विरासत भी बन जाता है। नानी की दी हुई चूड़ियां, मां का शादी वाला हार या दादी की पुरानी नथ केवल गहने नहीं होते, बल्कि वे पीढ़ियों की कहानियां अपने भीतर समेटे रहते हैं। कई परिवारों में आज भी शादी के समय पुराने गहनों को नई डिजाइन में तैयार करवाकर बेटी को दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन गहनों में केवल सोने की कीमत नहीं, बल्कि परिवार की भावनाएं और आशीर्वाद जुड़े होते हैं। यही कारण है कि भारतीय महिलाओं के लिए गहनों का महत्व केवल फैशन तक सीमित नहीं रहता।

समय बदलने के साथ महिलाओं की भूमिका भी बदली है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने फैसले खुद लेने लगी हैं। इसके बावजूद सोने का महत्व कम नहीं हुआ है। बल्कि अब सोने को परंपरा और निवेश दोनों रूपों में देखा जाने लगा है। लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं क्योंकि समय के साथ इसकी कीमत बढ़ती रहती है। कई परिवारों में आज भी बेटी के जन्म से ही उसके लिए थोड़ा-थोड़ा सोना जोड़ना शुरू कर दिया जाता है। यह परंपरा केवल सामाजिक दबाव नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा की भावना से जुड़ी होती है। भारतीय शादियों में सोने का एक सामाजिक पक्ष भी है। यहां गहनों को परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। शादी के दौरान दिए गए गहने केवल दुल्हन की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि परिवार अपनी बेटी को सम्मान और सुरक्षा के साथ विदा कर रहा है। हालांकि बदलते समय में इस सोच पर कई सवाल भी उठे हैं। कई बार सोने और दहेज की परंपरा ने सामाजिक बोझ का रूप ले लिया, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ा। लेकिन इसके बावजूद यदि परंपरा के मूल भाव को देखा जाए तो उसका उद्देश्य बेटी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, न कि किसी प्रकार का प्रदर्शन करना।

आज के दौर में जब फैशन तेजी से बदल रहा है, तब भी भारतीय शादी में सोने की चमक कम नहीं हुई है। आधुनिक डिजाइन, हल्की जूलरी और ट्रेंडी स्टाइल्स आने के बाद भी गोल्ड जूलरी का आकर्षण बना हुआ है। दुल्हन चाहे मॉडर्न लुक अपनाए या ट्रेडिशनल, उसके श्रृंगार में सोना किसी न किसी रूप में जरूर शामिल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना भारतीय मानसिकता और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक धातु नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है।

भारतीय परिवारों में सोना रिश्तों की गर्माहट का भी प्रतीक माना जाता है। जब मां अपनी बेटी को शादी में गहने पहनाती है तो उसमें केवल परंपरा नहीं होती, बल्कि उसके भीतर एक भावनात्मक सुरक्षा भी छिपी होती है। वह यह महसूस करती है कि बेटी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसके पास कुछ ऐसा जरूर रहेगा जो उसका अपना होगा। यही भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यही कारण है कि दादी-नानी की बातें आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं।

सोने का संबंध भारतीय समाज में शुभता से भी जोड़ा गया है। त्योहारों, पूजा-पाठ और विशेष अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे पर्वों पर लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि यह समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। शादी जैसे पवित्र अवसर पर इसका महत्व और बढ़ जाता है। दुल्हन का सोने से सजा होना केवल उसकी सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वह अपने नए जीवन की शुरुआत शुभता और सौभाग्य के साथ कर रही है।

आज भले ही समाज आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन भारतीय शादियों में सोने की परंपरा अब भी उतनी ही मजबूत है। इसकी वजह केवल फैशन या सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि वह गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ता है जो सदियों से भारतीय परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। सोना यहां केवल धातु नहीं, बल्कि रिश्तों की चमक, परिवार की यादों, मां-बाप की चिंता, दादी-नानी के अनुभव और बेटी के भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है।

भारतीय शादी में दुल्हन का सोना केवल उसके श्रृंगार का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वह उसके आत्मविश्वास, सम्मान और सुरक्षा का भी प्रतीक होता है। यही कारण है कि समय बदलने के बावजूद सोने की अहमियत कम नहीं हुई। यह परंपरा आज भी उसी चमक के साथ जीवित है क्योंकि इसमें केवल धन नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कारों और पीढ़ियों की विरासत की चमक शामिल है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

समुद्र पर सपनों का बांध: कल्पसर परियोजना से गुजरात की जल क्रांति को मिलने जा रही नई दिशा

गांधीनगर। गुजरात की दशकों पुरानी और देश की सबसे महत्वाकांक्षी जल परियोजनाओं में शामिल कल्पसर योजना अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री Narendra Modi के हालिया नीदरलैंड दौरे ने इस बहुचर्चित परियोजना को नई ऊर्जा और वैश्विक तकनीकी सहयोग का मजबूत आधार दे दिया है। समुद्री जल प्रबंधन और बांध निर्माण में दुनिया की अग्रणी विशेषज्ञता रखने वाले नीदरलैंड के साथ भारत ने तकनीकी सहयोग का महत्वपूर्ण आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है, जिससे गुजरात की इस विशाल परियोजना को साकार करने की दिशा में नई उम्मीदें जागी हैं। लंबे समय से तकनीकी जटिलताओं और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण धीमी गति से आगे बढ़ रही कल्पसर परियोजना अब अंतरराष्ट्रीय अनुभव और आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक के सहारे तेजी पकड़ सकती है।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अपने नीदरलैंड दौरे के दौरान वहां की विश्व प्रसिद्ध जल प्रबंधन संरचना Afsluitdijk का दौरा किया। यह वही विशाल बैरियर डैम है जिसे दुनिया जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में इंजीनियरिंग का चमत्कार मानती है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां उपयोग की गई तकनीकों का विस्तार से अध्ययन किया और उन्हें भारत के लिए सीखने योग्य बताया। खास बात यह है कि Afsluitdijk और गुजरात की कल्पसर परियोजना के बीच कई तकनीकी समानताएं हैं। दोनों परियोजनाओं का मूल उद्देश्य समुद्र के खारे पानी को नियंत्रित कर विशाल मीठे पानी के भंडारण की व्यवस्था तैयार करना है।

प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच हुए इस समझौते को केवल एक औपचारिक करार नहीं, बल्कि गुजरात की जल सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक संरचना से जुड़ा बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में विशाल बांध निर्माण, ज्वारीय दबाव नियंत्रण, मीठे पानी के संरक्षण और तटीय इंजीनियरिंग में नीदरलैंड का दशकों पुराना अनुभव भारत के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।

गुजरात लंबे समय से अनियमित बारिश, सूखे और जल संकट जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। हालांकि Sardar Sarovar Dam के निर्माण ने राज्य को बड़ी राहत दी, लेकिन भविष्य की जल आवश्यकताओं और बढ़ती आबादी को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार यह मानते रहे हैं कि केवल एक परियोजना पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसी सोच के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कल्पसर परियोजना की संकल्पना की थी। उनका उद्देश्य था कि समुद्र में बहकर नष्ट हो रहे नदियों के विशाल जल संसाधन को संरक्षित कर गुजरात को दीर्घकालिक जल सुरक्षा प्रदान की जाए।

कल्पसर परियोजना का मूल विचार खंभात की खाड़ी पर एक विशाल बांध बनाकर समुद्र में गिरने वाली सात नदियों के पानी को संरक्षित करना है। इस परियोजना के तहत खाड़ी के भीतर मीठे पानी का एक विशाल जलाशय विकसित किया जाएगा। यह केवल जल संरक्षण योजना नहीं, बल्कि बहुआयामी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसमें सिंचाई, पेयजल, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, परिवहन संपर्क और औद्योगिक विकास को एक साथ जोड़ा गया है। यदि यह परियोजना पूरी तरह साकार होती है, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी जल प्रबंधन योजनाओं में शामिल हो सकती है।

कल्पसर परियोजना का महत्व केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से सौराष्ट्र क्षेत्र के नौ जिलों की 42 तहसीलों को लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और लंबे समय से पानी की कमी झेल रहे किसानों को स्थायी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी लगभग 240 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 60 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे परिवहन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में भी यह परियोजना गुजरात के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। परियोजना के तहत लगभग 1500 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा तटीय पर्यटन, मत्स्य पालन और समुद्री व्यापार को भी इससे नई दिशा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कल्पसर केवल जल परियोजना नहीं, बल्कि गुजरात के आर्थिक और औद्योगिक भविष्य को बदलने वाली बहुआयामी विकास योजना है।

हालांकि इस परियोजना को जमीन पर उतारना आसान नहीं रहा है। समुद्री पारिस्थितिकी, ज्वारीय प्रभाव, तकनीकी जटिलताएं और पर्यावरणीय संतुलन जैसी चुनौतियों ने इसे अत्यंत कठिन परियोजना बना दिया। वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री Narendra Modi ने भावनगर में समुद्री सर्वेक्षण का शुभारंभ कर इस योजना को औपचारिक दिशा दी थी। इसके बाद समय-समय पर विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और तकनीकी मूल्यांकन किए गए। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में समुद्री इंजीनियरिंग और क्लोजर मेथेडोलॉजी पर विश्व प्रसिद्ध डच संस्था Royal HaskoningDHV ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री Bhupendra Patel ने भी गांधीनगर में नीदरलैंड की राजदूत Marisa Gerards के साथ बैठक कर कल्पसर परियोजना पर विस्तार से चर्चा की थी। इस दौरान इंडो-डच विशेषज्ञ समूह के गठन और सरकार-से-सरकार साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। यह स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि गुजरात सरकार और केंद्र दोनों इस परियोजना को लेकर गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं।

दूसरी ओर Afsluitdijk परियोजना की सफलता आज भी पूरी दुनिया के लिए उदाहरण मानी जाती है। लगभग 32 किलोमीटर लंबा यह बैरियर डैम उत्तरी सागर को मीठे पानी की झील से अलग करता है और नीदरलैंड के बड़े हिस्से को बाढ़ से बचाने का काम करता है। लगभग 80 वर्ष पहले निर्मित इस परियोजना ने यह साबित किया कि समुद्र के भीतर भी विशाल जल संरचनाएं बनाकर जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समुद्र के खारे पानी को रोककर भीतर विशाल मीठे पानी का भंडार तैयार करता है। साथ ही इसमें परिवहन, जहाजरानी और ऊर्जा उत्पादन जैसी सुविधाएं भी एकीकृत रूप से विकसित की गई हैं।

भारत और नीदरलैंड के बीच यह सहयोग केवल तकनीकी साझेदारी नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और भविष्य की जल चुनौतियों से निपटने की साझा रणनीति भी माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों ने जल प्रबंधन नवाचार, जलवायु अनुकूलन और सतत अवसंरचना विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीदरलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता और गुजरात की विकास दृष्टि का यह संगम सफल होता है, तो कल्पसर परियोजना केवल राज्य की जल समस्या का समाधान नहीं करेगी, बल्कि भारत के जल प्रबंधन मॉडल को भी वैश्विक पहचान दिला सकती है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की इस परियोजना को लेकर लगातार सक्रियता यह संकेत देती है कि सरकार इसे केवल एक सपना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में धरातल पर उतरने वाली ऐतिहासिक परियोजना के रूप में देख रही है। गुजरात के लिए यह परियोजना भविष्य की जल सुरक्षा, आर्थिक विकास और सतत ऊर्जा उत्पादन की नई आधारशिला साबित हो सकती है।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल के जूनागढ़ स्टेशन पर निःशुल्क छाछ का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में शुक्रवार को जूनागढ़ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क छाछ वितरण की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों को छाछ उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क छाछ वितरण सेवा में "आयुष हॉस्पिटल-जूनागढ़" का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। "आयुष हॉस्पिटल-जूनागढ़"ने यात्रियों के लिए निःशुल्क 200 लीटर छाछ की व्यवस्था की।

स्टेशन पर इन व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

पश्चिम रेलवे के 14 कर्मचारियों को महाप्रबंधक,संरक्षा पुरस्कार से किया गया सम्मानित

मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद एवं भावनगर मंडलों के कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय द्वारा मार्च 2026 के लिए 14 कर्मचारियों को महाप्रबंधक "मैन ऑफ द मंथ" संरक्षा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। इन कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के लिए सम्मानित किया गया, जिससे संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। सम्मानित कर्मचारियों में मुंबई सेंट्रल मंडल से 5, अहमदाबाद मंडल से 4, वडोदरा मंडल से 3 तथा भावनगर मंडल से 2 कर्मचारी शामिल थे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल के पांच कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान उनकी उत्कृष्ट सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

ट्रेन मैनेजर श्री अजय कुमार शिवशंकर प्रसाद ने ट्रेन का चार्ज लेते समय असाधारण सतर्कता का परिचय दिया। उन्होंने एक वैगन के नीचे पहिये की असामान्य स्थिति देखी, जो ट्रेन परिचालन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती थी तथा जिससे पटरी से उतरने की आशंका थी। उन्होंने तुरंत संबंधित

अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई। उनकी समय पर दी गई सूचना एवं सतर्कता से संभावित दुर्घटना टल गई तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ।

वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर (पैसेंजर) श्री विनोद कुमार को भरूच स्टेशन पर ट्रेन संख्या 69172 भरूच–सूरत मेमू में ड्यूटी के दौरान उनकी सूझबूझ के लिए सम्मानित किया गया। ट्रेन के प्रस्थान के समय उन्होंने एक 70 वर्षीय यात्री को चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय घिसटते हुए देखा। श्री विनोद कुमार ने तुरंत गार्ड इमरजेंसी ब्रेक लगाया तथा मोटरमैन को सतर्क किया, जिससे ट्रेन तुरंत रुक गई और यात्री को सुरक्षित बचा लिया गया। उनकी त्वरित कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई तथा यात्री सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा गया।

पॉइंट्समैन श्री भरत आई. पटेल को भी उनकी सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने रेल फ्रैक्चर का पता चलते ही तुरंत ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन अधीक्षक को सूचित किया। उस समय कर्णावती एक्सप्रेस स्टेशन की ओर आ रही थी, जिसे उत्राण स्टेशन पर रोका गया। इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा ट्रैक की मरम्मत की गई तथा गति प्रतिबंध के साथ ट्रेन परिचालन बहाल किया गया। उनकी समय पर की गई कार्रवाई एवं संरक्षा के प्रति सजगता से एक बड़ी अप्रिय घटना टल गई।

सहायक खलासी श्री मधुबन यादव को वसई रोड स्टेशन पर एक ट्रेन की रोलिंग-इन जांच के दौरान उनकी असाधारण सतर्कता एवं सजगता के लिए सम्मानित किया गया। ड्यूटी के दौरान उन्होंने ट्रेन के कई वैगनों में लोडेड एचआर कॉयल्स की लाशिंग टूटी हुई एवं अनुचित पाई। इस दोष की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी गई तथा आवश्यक कार्रवाई की गई। उनकी त्वरित पहचान एवं समय पर दी गई सूचना से संभावित दुर्घटना टल गई तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ। उनकी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता एवं संरक्षा चेतना की सराहना की गई।

वरिष्ठ सहायक लोको पायलट श्री लोकेश मीणा को भी परिचालन संरक्षा के प्रति असाधारण सतर्कता एवं समर्पण प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया। वे ट्रेन संख्या 14707 रणकपुर एक्सप्रेस में सूरत से दादर के मध्य कार्यरत थे। सूरत स्टेशन पर लोकोमोटिव निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि पावर कार के हेड-ऑन जनरेशन सिस्टम का इंटर व्हीक्यूलर कपलर खुल गया था और खतरनाक रूप से ट्रैक पर लटक रहा था, जिससे ट्रेन परिचालन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत लोको पायलट एवं पावर कार स्टाफ को सूचित किया, जिसके बाद तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई कर दोष को दूर किया गया। उनकी असाधारण सतर्कता, सूझबूझ एवं समय पर की गई कार्रवाई से संभावित गंभीर दुर्घटना टल गई तथा सुरक्षित एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ।

वडोदरा, अहमदाबाद एवं भावनगर मंडलों के कर्मचारियों को भी रेल फ्रैक्चर, ट्रैक में अनियमितताओं आदि जैसे संरक्षा संबंधी खतरों की समय पर पहचान एवं निराकरण के लिए सम्मानित किया गया। उनकी त्वरित कार्रवाई ने सम्पूर्ण नेटवर्क पर सुरक्षित रेल परिचालन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पश्चिम रेलवे सभी सम्मानित कर्मचारियों के कर्तव्य के प्रति समर्पण, व्यावसायिकता एवं सुदृढ़ संरक्षा चेतना की सराहना करता है। इनके सराहनीय कार्यों से न केवल संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सका, बल्कि सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल परिचालन के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई है। साथ ही, ये कर्मचारी अन्य रेलकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026" के तहत मंडल रेल प्रबंधक ने दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ

भारतीय रेल द्वारा 15 मई से 5 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 18 मई 2026 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश ने मंडल कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता तथा प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के प्रति प्रतिज्ञा दिलाई। शपथ के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने, जल एवं ऊर्जा की बचत करने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा हरित एवं सतत जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी, स्वच्छता, जल एवं ऊर्जा संरक्षण तथा सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों, कार्यालय परिसरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रभात फेरियां, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाएं, जागरूकता रैलियां,

प्रतियोगिताएं तथा सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

15 मई से 5 जून 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान रेलवे परिसरों, पटरियों एवं जल स्रोतों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही "एक पेड़ मां के नाम" पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। "सिंगल यूज़ प्लास्टिक" के उपयोग को कम करने तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विशेष जन-जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे।

यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग अपनाने, पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलों तथा कपड़े एवं जूट के बैगों के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाओं, जागरूकता रैलियों, प्रतियोगिताओं एवं सामाजिक सहभागिता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

5 जून 2026 को "विश्व पर्यावरण दिवस" के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर आगे बढ़ाते हुए समाज में पर्यावरण जागरूकता फैलाने हेतु सतत कार्य करता रहेगा। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने तथा स्वच्छ एवं हरित भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

लखीमपुर-बहराइच हाईवे पर लगा शवों का ढेर

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर-नानपारा मार्ग पर सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में दो महिलाओं समेत 10 मजदूरों की मौत हो गई। ईसानगर थाना क्षेत्र में अदलीसपुर के मजरा भरेहटा के पास तेज रफ्तार ट्रक और सवारी मैजिक वाहन की आमने-सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैजिक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई।

जानकारी के अनुसार मजदूरी कर सभी श्रमिक मैजिक वाहन से लखीमपुर से बहराइच के नानपारा लौट रहे थे। सुबह करीब सात बजे हुए हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को सरकारी एंबुलेंस से सीएचसी खमरिया पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने आठ लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार हादसे में मैजिक सवार सभी 10 लोगों की मौत हुई है, जिनमें आठ पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की पहचान जयवीर सिंह (25), पवन कुमार, सोहन (21), अदनान (19), राजेश गोयल (45), सहजराम (35), पप्पू (18), गायत्री वैश्य (44), जुलेखा (55) और कलैश वर्मा (40) के रूप में हुई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने मौके और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से गुजरात कैडर में आवंटित 2025 बैच के 8 प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों ने मुलाकात की

बावन सप्ताह के जिला प्रशिक्षण से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ सोमवार को गुजरात कैडर में आवंटित 2025 की भारतीय सिविल सेवा बैच के 8 प्रोबेशनरी अधिकारियों ने गांधीनगर में शिष्टाचार मुलाकात की।

ये प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में फाउंडेशन कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण करके गुजरात कैडर में सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। उन्हें बावन सप्ताह के जिला प्रशिक्षण के लिए बनासकांठा, भरूच, अमरेली, कच्छ, पंचमहल, गोधरा, वलसाड, राजकोट और महीसागर जिले आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मुलाकात के दौरान प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए सामान्य नागरिक तथा वंचित गरीबों के कल्याण के सेवा संकल्प के

साथ सेवारत रहने की सीख दी। ये अधिकारी जिला प्रशिक्षण के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण, वन डिस्ट्रिक्ट - वन प्रोडक्ट, सोशल एंड फाइनेंशियल इन्क्लूजन, गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, मैनेजमेंट जैसे विविध विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण से पूर्व ये अधिकारी चार सप्ताह के लिए स्पीपा अहमदाबाद में संस्थागत प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो 26 मई को पूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री से मिले इन प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों ने यह भावना भी व्यक्त की कि स्पीपा का प्रशिक्षण उनके करियर निर्माण में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान स्पीपा के महानिदेशक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला, निदेशक श्री चंद्रेश कोटक तथा स्पीपा के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे-रतलाम

"ई-निविदा सूचना"

क्र. सं. 1. ई–टेंडरिंगः RTM-2026-27-32 | कार्य का नामः Ratlam (LCC) Upgradation of Traction Training centre of locomotive care centre at (Composite Civil + Electrical) | अनुमानित मात्राः As per tender schedule | अनुमानित लागतः 6,29,25,510.10 | बयाना राशीः 12,58,500.00 | कार्य समापन अवधिः 12 Months | वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथिः 15.05.2026 | निविदा खुलने की की तिथिः 10.06.2026 | क्र. सं. 2. ई–टेंडरिंगः RTM-2026-27-33 | कार्य का नामः Rajendra Nagar Station Provision of fencing between UP Main Track & DN Main Track to avoid tresspassing | अनुमानित मात्राः As per tender schedule | अनुमानित लागतः 34,99,848.24 | बयाना राशीः 70,000.00 | कार्य समापन अवधिः 06 Months | वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथिः 15.05.2026 | निविदा खुलने की तिथिः 10.06.2026 | विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं। 0058

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

स्टोर्स डिपार्टमेंट

जून 2026 के दौरान P-Way और दूसरे अलग-अलग तरह के स्क्रैप के लिए ई-ऑक्शन सेल

विशेष ध्यान: सभी स्टील खरीदार और री-रोलर

P. Way सड़क स्क्रैप, रेल स्क्रैप और दूसरे स्क्रैप मटीरियल के डिस्पोज़ल के लिए पब्लिक ई-ऑक्शन जून 2026 में नीचे दिए गए शेड्यूल के हिसाब से होगा:

पहला दौर	दूसरा दौर	डिपो/डिवीजन	प्रभारी अधिकारी	संपर्क संख्या
02/06/2026	16/06/2026	रतलाम	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - रतलाम	07412230080 09752492750
04/06/2026	18/06/2026	वडोदरा	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - वडोदरा	02652641592 09724091750
05/06/2026	19/06/2026	अहमदाबाद	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - अहमदाबाद	07922205888 09724093750
05/06/2026	22/06/2026	दाहोद	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - दाहोद	02673241295 09724090455
08/06/2026	22/06/2026	मुंबई सेंट्रल	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - मुंबई	022-23094142 09004499006
09/06/2026	23/06/2026	प्रतापनगर	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - प्रतापनगर	02652641592 09724091750
11/06/2026	24/06/2026	राजकोट	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - राजकोट	02812476943 09724094770
11/06/2026	24/06/2026	साबरमती	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - साबरमती	07927500080 09724093774
12/06/2026	25/06/2026	महालक्ष्मी	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - महालक्ष्मी	022-24929571 09004495750
12/06/2026	25/06/2026	पारडी	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - MX	022-24929571 09004495750
12/06/2026	25/06/2026	भावनगर	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - भावनगर	02782444360 09724097750

ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया संबंधित डिपो/डिवीजनल ऑफिसर से संपर्क करें। नोट:-1. रेलवे के पास ई-ऑक्शन से किसी भी लॉट को वापस लेने का अधिकार है। 2. ई-ऑक्शन तय समय पर शुरू होगा। 3. ई-ऑक्शन कैटलॉग ई-ऑक्शन पोर्टल www.ireps.gov.in पर उपलब्ध होगा। 4. ई-ऑक्शन, डिजिटल सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और हिस्सा लेने के बारे में किसी भी मदद के लिए, कृपया ऊपर दिए गए डिपो/डिवीजनल ऑफिसर से संपर्क करें। 5. सभी पेमेंट ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ज़रिए किए जाएंगे।

(No. S/SIII/ऑक्शन प्रोग्राम-1/JUNE2026, तारीख 21.05.2026) 0107

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें: twitter.com/WesternRly

सूरत में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का भविष्य: 'टेक्निकल टेक्सटाइल्स कॉन्क्लेव 2026' ने उद्योग को दिया नया विज़न, वैश्विक अवसरों पर जोर

सूरत। भारत की टेक्सटाइल राजधानी माने जाने वाले सूरत में एक बार फिर उद्योग जगत के भविष्य को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। सरसाना स्थित यूकेएम हॉल में आयोजित 'टेक्निकल टेक्सटाइल्स कॉन्क्लेव 2026' ने न केवल पारंपरिक टेक्सटाइल उद्योग को नई सोच दी, बल्कि इसे वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश कराने का स्पष्ट संदेश भी दिया। यह आयोजन Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI) और Indian Technical Textile Association (ITTA) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग को पारंपरिक उत्पादन से आगे बढ़ाकर तकनीक-आधारित, उच्च मूल्य संवर्धित और वैश्विक मांग के अनुरूप उद्योग के रूप में विकसित करना था। "स्मार्टर टुमॉरो के लिए टेक्सटाइल में इनोवेशन" थीम पर आधारित इस आयोजन में देशभर से आए उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और व्यापारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि अब टेक्सटाइल उद्योग केवल कपड़े बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा, चिकित्सा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल और अंतरिक्ष तकनीक तक अपनी भूमिका का विस्तार कर चुका है। विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले दशक में टेक्निकल टेक्सटाइल्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक होगा।

कार्यक्रम में Ashok Jirawala ने अपने संबोधन में कहा कि सूरत का टेक्सटाइल उद्योग अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक यार्न और फैब्रिक के साथ-साथ अब उद्योगपतियों को तकनीकी वस्त्रों की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यही भविष्य की वास्तविक मांग है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वे केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि नवाचार, अनुसंधान और मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करें। उनके अनुसार, जो उद्योग तकनीक को अपनाएंगे, वही आने वाले वर्षों में वैश्विक बाजार में टिक पाएंगे।

इस अवसर पर Dr. Nandan Kumar ने कहा कि भारत का एमएसएमई सेक्टर टेक्सटाइल उद्योग की रीढ़ है, लेकिन अब इसे पॉलिमर आधारित उत्पादन से आगे बढ़कर हाई-परफॉर्मेंस फाइबर और तकनीकी सामग्री की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि एक नवाचार आधारित आर्थिक मॉडल है, जिसमें अनुसंधान और विकास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उद्योग और अकादमिक संस्थान मिलकर अनुसंधान को उत्पादन से जोड़ें। इससे न केवल

गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की पहचान भी मजबूत होगी।

पूर्व एडिशनल टेक्सटाइल कमिश्नर S. P. Verma ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स के वैश्विक परिदृश्य पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत उपयोग मैन-मेड फाइबर (MMF) का होता है, जो भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि सूरत पहले से ही MMF उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहां से टेक्निकल टेक्सटाइल्स में प्रवेश करना सबसे स्वाभाविक और लाभकारी कदम होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत उच्च गुणवत्ता वाले परफॉर्मेंस यार्न का उत्पादन शुरू कर देता है, तो देश इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति हासिल कर सकता है। उन्होंने उद्योगपतियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते तकनीकी बदलाव नहीं अपनाया गया, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का खतरा बढ़ सकता है।

कार्यक्रम में सरकार और नीति निर्माण से जुड़े पहलुओं पर भी गहन चर्चा हुई। J. B. Dave ने गुजरात सरकार की टेक्सटाइल नीति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार टेक्निकल टेक्सटाइल्स को विशेष प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए कई प्रकार की वित्तीय सहायता योजनाएं लागू की गई हैं।

उन्होंने बताया कि कैपिटल सब्सिडी, पावर सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ उद्योगों को मिल रहा है, जिससे निवेशकों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने वाले उद्योगों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक दक्षता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले समय में यूरोपीय संघ जैसे बाजारों में कार्बन टैक्स जैसे नियम लागू होने से निर्यात पर असर पड़ सकता है। इसलिए उद्योगों को अभी से अपने उत्पादन सिस्टम को पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल बनाना होगा।

कॉन्क्लेव के दौरान चार महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। पहला सत्र डायवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी पर आधारित था, जिसमें वैल्यू-एडेड टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अवसरों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि उद्योग को केवल मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता और तकनीकी मूल्य पर ध्यान देना चाहिए।

दूसरे सत्र में डिफेंस एप्लीकेशन पर चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि रक्षा क्षेत्र में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जैसे बुलेटप्रूफ जैकेट, सैन्य उपकरण, सुरक्षा कपड़े और हाई-टेक यूनिफॉर्म। इस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

तीसरे सत्र में जियो टेक्सटाइल्स और बिल्डिंग टेक्सटाइल्स पर चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि सड़क निर्माण, बांध, सुरंग, पुल और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह न केवल निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि स्थायित्व और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

चौथे सत्र में स्पोर्टेक और स्टैंडर्डाइजेशन पर चर्चा हुई। इसमें खेलों में उपयोग होने वाले तकनीकी कपड़ों, सुरक्षा उपकरणों और प्रदर्शन सुधारने वाले टेक्सटाइल्स पर फोकस किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक खेल उद्योग में टेक्निकल टेक्सटाइल्स की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत इसमें बड़ा खिलाड़ी बन सकता है।

इन सभी सत्रों में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। यह क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

कार्यक्रम के अंत में Dr. Dhaval Patel और Anil Kumar Vasu Pillai ने सभी अतिथियों, विशेषज्ञों और उद्योगपतियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कॉन्क्लेव उद्योग और नीति निर्माण के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं और भविष्य की दिशा तय करने में मदद करते हैं।

सूरत और दक्षिण गुजरात के बड़ी संख्या में टेक्सटाइल उद्योगपतियों की उपस्थिति ने यह साबित किया कि क्षेत्र अब तेजी से बदलाव के लिए तैयार है। पारंपरिक टेक्सटाइल हब अब तकनीकी टेक्सटाइल्स के वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर यह कॉन्क्लेव केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि यह सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य की रूपरेखा थी, जो आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक टेक्सटाइल शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

लिंबायत ज़ोन में विकास कार्यों की समीक्षा, सूरत नगर निगम ने तेज की मॉनसून तैयारी और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग

सूरत। शहर के विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से Surat Municipal Corporation के लिंबायत ज़ोन कार्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता म्युनिसिपल कमिश्नर M. Nagarajan ने की, जिसमें ज़ोन स्तर पर चल रहे सभी प्रमुख विकास कार्यों, मॉनसून पूर्व तैयारियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक की शुरुआत में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान ब्रिज, ड्रेनेज, हाइड्रोलिक, हेल्थ, रोड्स, गार्डन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक विभागों के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। कमिश्नर ने प्रत्येक विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट्स की स्थिति, समयसीमा और गुणवत्ता मानकों पर विस्तार से जानकारी ली और जहां भी देरी या कमी पाई गई, वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए।

बैठक में विशेष रूप से उन विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई जो वर्तमान में प्रगति पर हैं या हाल ही में पूरे किए गए हैं। इनमें कम्युनिटी हॉल, स्कूल भवनों का विकास, रीडिंग रूम, गार्डन, योगा स्टूडियो और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। कमिश्नर ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाजनक शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है।

मॉनसून को ध्यान में रखते हुए बैठक का एक बड़ा हिस्सा पूर्व-मानसून तैयारियों को समर्पित रहा। लिंबायत ज़ोन से गुजरने वाली खाड़ियों और नालों की सफाई,

जल निकासी व्यवस्था की मजबूती और संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान पर विस्तार से चर्चा की गई। Surat Municipal Corporation के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी ड्रेनेज सिस्टम को समय रहते पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए ताकि भारी बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

बैठक में तकनीकी, गैर-तकनीकी और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और एकीकृत योजना के तहत काम करने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर M. Nagarajan ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और हर परियोजना की प्रगति पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

बैठक के दौरान ज़ोन की वित्तीय स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को आय बढ़ाने के नए स्रोत तलाशने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि नगर निगम की परियोजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता दोनों को प्राथमिकता दी जाए ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।

सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सभी कार्यों की नियमित निगरानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से की जाए और तय समयसीमा में उन्हें पूरा किया जाए।

इसके अलावा डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। बैठक में कहा गया कि प्रशासनिक स्वीकृतियों और फाइल प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम का अधिकतम उपयोग किया जाए ताकि काम में तेजी आए और पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही ज़ोन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए।

अंत में म्युनिसिपल कमिश्नर M. Nagarajan ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टीमवर्क और समन्वय के साथ कार्य करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही और सक्रियता आवश्यक है।

इस समीक्षा बैठक को शहर के विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में लिंबायत ज़ोन के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने में मदद करेगा।

डिजिटल भारत की ओर कदम: सूरत में 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' अभियान को मिला जनसमर्थन, नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील

सूरत। देश की सबसे बड़ी सांख्यिकीय कवायद Census 2027 के पहले चरण की शुरुआत के साथ ही डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' प्रक्रिया को लेकर सूरत में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी क्रम में गुजरात के उपमुख्यमंत्री Harsh Sanghavi ने नागरिकों से अपील करते हुए इस डिजिटल जनगणना अभियान को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया है।

सूरत में इस अभियान के दौरान उपमुख्यमंत्री Harsh Sanghavi ने स्वयं अपने घर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर डिजिटल प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने इसे एक उदाहरणात्मक कदम बताते हुए कहा कि जब जनप्रतिनिधि स्वयं इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो जनता में विश्वास और जागरूकता दोनों बढ़ते हैं। उनका यह कदम डिजिटल भारत की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अपील की कि सभी लोग इस प्रक्रिया को केवल एक औपचारिकता न समझें, बल्कि इसे देश के विकास की नींव से जोड़कर देखें। उन्होंने कहा कि Census 2027 केवल जनसंख्या का आंकड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश की भविष्य की योजनाओं का आधार है। इसी डेटा के आधार पर सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियों को तैयार करती हैं।

उपमुख्यमंत्री Harsh Sanghavi ने कहा कि यदि डेटा सही और सटीक होगा,

तो नीतियां भी अधिक प्रभावी होंगी और समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ समान रूप से पहुंचेगा। उन्होंने इसे "सही जनगणना, मजबूत भारत की दिशा में निर्णायक कदम" बताया। उनका कहना था कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से अब यह प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित हो गई है। अभियान के तहत 15 मई से 31 मई तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। इस 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' प्रणाली का उद्देश्य लोगों को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना और जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि मानव संसाधन पर भी दबाव कम होगा।

इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अभियान की महत्ता को रेखांकित किया। बैठक और कार्यक्रम में M. Nagarajan सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल जनगणना प्रणाली से डेटा संग्रहण की गुणवत्ता में सुधार होगा और गलतियों की संभावना कम होगी।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी नागरिक से ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करने की अपील की गई है। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जी कॉल से सतर्क रहें। Harsh Sanghavi ने विशेष रूप से कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।

सूरत में इस अभियान को लेकर लोगों में धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है। नगर निगम, प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों की मदद से इसे व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है। स्कूलों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर भी डिजिटल जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह अभियान सफल होता है, तो यह भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। इससे न केवल डेटा संग्रहण की प्रक्रिया आधुनिक होगी, बल्कि नीति निर्माण में भी सटीकता आएगी। फिलहाल सूरत में यह अभियान गति पकड़ रहा है और प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक नागरिक इसमें भाग लेकर डिजिटल भारत के इस महत्वपूर्ण मिशन को सफल बनाएंगे।

सोना वायदा में 829 रुपये, चांदी वायदा में 3775 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 54 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 228926.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 38834.31 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 190092.44 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 38500 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3037.34 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 28170.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 158076 रुपये के भाव पर खूलकर, 159540 रुपये के दिन के उच्च और 157547 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158547 रुपये के पिछले बंद के सामने 829 रुपये या 0.52 फीसदी की बढ़त के साथ 159376 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 292 रुपये या 0.23 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 127693 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 41 रुपये या 0.26 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15999 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जून वायदा 157690 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159040 रुपये और नीचे में 157175 रुपये पर पहुंचकर, 737 रुपये या 0.47 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 157160 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159221 रुपये और नीचे में 157159 रुपये पर पहुंचकर, 158404 रुपये के पिछले बंद के सामने 736 रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 159140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सत्र के आरंभ में 267400 रुपये के भाव पर खूलकर, 276764 रुपये के दिन के उच्च और 264949 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 271886 रुपये के पिछले बंद के सामने 3775 रुपये या 1.39 फीसदी की मजबूती के साथ 275661 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 4111 रुपये या 1.5 फीसदी बढ़कर 278948 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 3973 रुपये या

1.45 फीसदी की तेजी के संग 278804 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 3901.15 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 1.4 रुपये या 0.1 फीसदी बढ़कर 1343 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 4.15 रुपये या 1.14 फीसदी की तेजी के संग 367.35 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 2.4 रुपये या 0.63 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 381.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 55 पैसे या 0.27 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 202.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 38834.31 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 190092.44 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 28170.21 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38500 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 6915.58 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 10302 रुपये के भाव पर खूलकर, 10412 रुपये के दिन के उच्च और 10056 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 54 रुपये या 0.54 फीसदी की बढ़त के साथ 10134 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 45 रुपये या 0.45 फीसदी की मजबूती के साथ 10126 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा 290.4 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 295.4 रुपये और नीचे में 289.8 रुपये पर पहुंचकर, 284 रुपये के पिछले बंद के सामने 9.1 रुपये या 3.2 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 293.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 9.1 रुपये या 3.21 फीसदी की मजबूती के साथ 293 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 994.8 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.2 रुपये या 0.22 फीसदी गिरकर 997.6 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 12663.24 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 15506.97 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2808.82 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 409.48 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 8.70 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 661.00 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4636.19 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2263.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10364 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 63605 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 19791 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 270930 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 42992 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9338 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22399 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 73416 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20451 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 32751 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा सत्र के आरंभ में 38500 पॉइंट पर खूलकर, 38500 के उच्च और 38500 के नीचले स्तर को छूकर, 58 पॉइंट घटकर 38500 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 11000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 16.5 रुपये की गिरावट के साथ 387.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.75 रुपये की बढ़त के साथ 5.05 रुपये हुआ।

सोना मई 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 28 रुपये की गिरावट के साथ 245.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 558 रुपये की बढ़त के साथ 2400 रुपये हुआ। तांबा मई 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.14 रुपये की गिरावट के साथ 3.3 रुपये हुआ। जस्ता मई 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3 पैसे की नरमी के साथ 0.45 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 30.6 रुपये की गिरावट के साथ 166.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.15 रुपये की गिरावट के साथ 7 रुपये हुआ। सोना मई 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 65 रुपये की गिरावट के साथ 369 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 220000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1 रुपये की बढ़त के साथ 376 रुपये हुआ। तांबा मई 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 16 पैसे की नरमी के साथ 5.99 रुपये हुआ। जस्ता मई 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.73 रुपये की गिरावट के साथ 1.21 रुपये हुआ।